उदयपुर में जलवायु परिवर्तन और बच्चों का पोषण

जलवायु परिवर्तन से दुनियाभर में खाद्य सुरक्षा और बच्चों के पोषण पर बहुत नकारात्मक असर पड़ रहा है, जिसकी कहानियां धीरे-धीरे हम सबके सामने आ रही है। उदयपुर भी इस से अछूता नहीं है। उदयपुर शहर और उस से लगते आस-पास के गांवों- कस्बों में अचानक आई तेज़ बारिश, भयंकर गर्मी, भू- जल के गिरते स्तर और बाढ़ के हालातों ने बच्चों के खान-पान को बहुत हद तक प्रभावित किया है। सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा क़ानून लागू किये गए है, किन्तु उसकी कई खामियों के चलते भी बच्चों और महिलाओं के पोषण और स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।

विगत दिनों उदयपुर में जलवायु बदलावों से बच्चों के विकास पर पड़ रहे असर को समझने के लिए ICLEI साउथ एशिया टीम द्वारा विभिन्न कमज़ोर तबकों के इलाकों में चर्चा की गयी और मौसम के बदलावों से बच्चों के स्वास्थ्य-पोषण पर हो रहे असर को समझने की कोशिश की गयी। इस दौरान सरकारी खाद्य आपूर्ति तंत्र, एकल परिवारों के प्रवास (माइग्रेशन) के पैटर्न और अचानक तेज़ बारिश-बाढ़ और सूखे से आस-पास के इलाकों में फसल की पैदावार और बच्चों के समग्र विकास पर इसके असर को समझने की कोशिश की गयी।

दक्षिणी राजस्थान; खासकर उदयपुर में बच्चों में कुपोषण और महिलाओं (खासकर युवा महिलाएं और किशोरियां- जो मां बनने की आयु में हैं) में एनीमिया की दर बहुत ज्यादा है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण ०५ के आंकड़ों को देखें तो लगभग आधी महिलाएं (४९.१%) खून की कमी से जूझ रही है। इस स्थिति में जलवायु परिवर्तन कोढ़ में खाज का काम करता है। महिलाएं उचित पोषण से वंचित रहती है और विपरीत मौसम में उन्हें अतिरिक्त काम करना पड़ता है, जिस से उन्हें जल्दी थकान और कमजोरी झेलनी पड़ती है। ऐसे में गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य-पोषण पर भी इसका नकारात्मक असर होता है। बच्चे अपने आरंभिक वर्षों में उचित विकास से वंचित रह जाते हैं। उदयपुर में कुपोषण की दर पहले से ही अधिक है। कई बच्चे बौनेपन, कमज़ोरी और सूक्ष्म पोषक तत्वों (माइक्रो न्युटरेंट्स) की कमी से पीड़ित हैं। जलवायु परिवर्तन और परिवारों का प्रवास विविध और पौष्टिक खाद्य पदार्थों तक पहुँच को सीमित करके इस समस्या को और बढ़ा देते हैं। लंबे समय तक सूखा पड़ने से फलों, सब्जियों और अन्य पोषक तत्वों से भरपूर फसलों की उपलब्धता कम हो जाती है, जबकि बाढ़ से खाद्य वितरण चैनल बाधित हो जाते हैं, जिससे परिवारों के लिए अपने बच्चों के लिए पर्याप्त आहार प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। इसके अतिरिक्त, प्रवासी बच्चों को अक्सर स्कूल-आधारित पोषण कार्यक्रमों तक निरंतर पहुँच की कमी होती है, जिससे उनकी पोषण संबंधी स्थिति और भी खराब हो जाती है। खाद्य सुरक्षा में केवल गेंहू मिलने के कारण प्रोटीन और वसा जैसे आवश्यक खाद्य तत्वों से भी बच्चे वंचित रहते हैं।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण ०५ के आंकड़े	भारत	राजस्थान	उदयपुर
नाटापन/ बौनापन/ Stunted *आयु के अनुसार लम्बाई में कमी (५ वर्ष तक के बच्चे)*	३५.५%	३१.८%	३४%
दुबलापन/ Wasted *लम्बाई के अनुसार वज़न में कमी (५ वर्ष तक के बच्चे)*	१९.३%	१६.८%	०९%
कम वज़न / Underweight *आयु के अनुसार वज़न में कमी (५ वर्ष तक के बच्चे)*	३२.१%	२७.६%	२७.४%
शिशु मृत्यु दर / IMR *प्रति १००० बच्चों पर मरने वाले शिशुओं की संख्या*	३५.५	३०	१६.८
महिलाओं में रक्ताल्पता/ एनीमिया	५७%	५५%	४९.१%

फ्रंटलाइन वर्कर की भागीदारी पर प्रभाव

जलवायु परिवर्तन द्वारा उत्पन्न एक और महत्वपूर्ण चुनौती आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा सहयोगिनी और एएनएम जैसे फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं द्वारा नियमित होम विजिट्स (दैनिक घर के दौरे) और सामुदायिक भागीदारी में कमी है। बाढ़ और तेज़गर्मी/ लू जैसी स्थिति के दौरान, उनकी विजिट्स पूरी तरह से रुक जाती है, जिससे ज़रूरी स्वास्थ्य और पोषण सेवाएँ प्रदान करने की उनकी क्षमता सीमित हो जाती है। इसका नकारात्मक असर गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और नवजात शिशुओं पर पड़ता है, जो नियमित जांच, टीकाकरण और पोषण संबंधी सहायता के लिए इन सेवाओं पर निर्भर रहते हैं। सामुदायिक स्तर पर हस्तक्षेप में कमी से मातृ और बाल कुपोषण की पहले से ही उच्च दर और बढ़ जाती है, जिससे खराब स्वास्थ्य परिणामों का चक्र और भी गहरा हो जाता है।

फिल्ड भ्रमण में स्थानीय समुदाय से बातचीत के दौरान शहर के अलीपुरा, कृष्णपुरा, नीमचमाता और माछला मगरा कच्ची बस्ती क्षेत्र की कई महिलाओं ने बताया कि साल २०१६ में जब तेज़ गर्मी पड़ी और उसके तत्काल बाद जब आयड नदी में १० दिन से ज्यादा तेज़ बहाव बना रहा, तब आंगनवाड़ी और स्वास्थ्य केन्द्रों से मिलने वाली सारी सुविधाएं लगभग बंद हो गयी थी और परिवारों को निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ा था, जिस में आने जाने और दवाइयों में उनकी बचत काफी हद तक खर्च हो गयी थी।

पलायन-प्रवास से पोषण पर प्रभाव

उदयपुर में आस-पास के गाँवों, छोटे शहरों, जिलों और यहाँ तक कि अन्य राज्यों से भी महत्वपूर्ण मात्रा में पलायन देखा गया है। इनमें से कई प्रवासी असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं, जिसमें निर्माण, घरेलू काम और छोटे पैमाने के उद्योग शामिल हैं। ये लोग अपने क्षेत्र में सरकारी योजनाओं का लाभ लेते हैं किन्तु जब उदयपुर आते हैं तो योजनाओं का लाभ बहुत पीछे छूट जाता है। हालाँकि सरकारें दावा करती हैं कि प्रवास के दौरान भी खाद्य सुरक्षा के लाभ मिलते हैं, किन्तु वास्तविकता इस से कोसों दूर हैं। अनियमित वितरण, सही लाभार्थी की पहचान, ऑनलाइन प्रक्रिया आदि कई ऐसे कारक हैं, जो इन्हें खाद्य सुरक्षा से बाहर कर देते हैं। साथ ही में दूसरे स्थानों से उदयपुर में बस रहे ये एकल परिवार खाद्य आपूर्ति प्रणालियों और सार्वजनिक सेवाओं, जिसमें पानी और स्वच्छता का बुनियादी ढांचा शामिल है, पर भी अतिरिक्त दबाव डालती है। प्रवासी परिवारों को उनकी अस्थिर आय तथा नए स्थानों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली या मिड-डे मील (मध्याह्न भोजन) जैसी सरकारी खाद्य सम्बन्धी योजनाओं तक पहुंच की कमी के कारण, विशेष रूप से खाद्य असुरक्षा और कुपोषण का खतरा रहता है।

कम आय में घर को चलाने में प्रवासी परिवारों की महिलाएं स्वयं और बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण में सबसे ज्यादा समझौते करती हैं। ऐसे में विपरीत जलवायु में इनकी परेशानियाँ कई गुना बढ़ जाती है. अगर पति और पत्नी- दोनों कमाने में व्यस्त है, तो छोटे बच्चों के साथ उनका समय बिता पाना लगभग नामुमकीन हो जाता है। ऐसे में बच्चे के विकास पर भी विपरीत असर पड़ता है। यह भी देखने में आया है कि कई बार बड़े बच्चे इसलिए स्कूल नहीं जा पाते, क्योंकि उन्हें अपने छोटे भाई-बहनों की देखभाल करनी होती है। इस स्थिति में पूरे परिवार पर इसका विपरीत असर पड़ना तय है। पहचान उजागर नहीं करने की शर्त पर एक आशा सहयोगिनी बताती है कि बदलते मौसम ने महिलाओं और बच्चों में चिड़चिड़ापन, तनाव और गुस्से को कई गुना बढ़ा दिया है। इस से घरों में स्वस्थ माहौल ख़त्म होता है और बड़ों में होने वाले झगड़े और पिटाई चंचल मन को मानसिक रूप से बहुत प्रभावित करती है, जिसका असर बच्चे के आने वाले वर्षों पर अवश्य ही प्रतिकूल होगा।

सरकारी खाद्य आपूर्ति तंत्र और उनकी भूमिका

खाद्य असुरक्षा को दूर करने के लिए सरकार ने कई योजनाएँ लागू की हैं, जिनमें मिड-डे मील कार्यक्रम, एकीकृत बाल विकास सेवाओं (ICDS) के तहत टेक होम राशन और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) शामिल हैं। ये कार्यक्रम यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं कि बच्चों को उनकी दैनिक पोषण आवश्यकताओं का कम से कम कुछ हिस्सा मिले। हालाँकि, जलवायु परिवर्तन और प्रवास इन सेवाओं के प्रभावी वितरण के लिए चुनौतियाँ पेश करते हैं।

- **मिड-डे मील (MDM) कार्यक्रम:** स्कूल अक्सर बच्चों के लिए पौष्टिक भोजन के प्राथमिक स्रोत के रूप में काम करते हैं। बाढ़ के दौरान, स्कूल बंद होने से मिड-डे मील की डिलीवरी बाधित होती है, जिससे बच्चों के पोषण में कमी आती है। प्रवासी बच्चे, खास तौर पर स्कूल न जाने वाले बच्चे, इस महत्वपूर्ण सुरक्षा जाल से वंचित रह जाते हैं।
  वर्ष २००६ और २०१६ में बाढ़ के दौरान आयड, लोहार बस्ती, अलीपुरा, गारियावास, भूपालपुरा मठ, खेमपुरा आदि क्षेत्रों में स्कूलों को दो हफ़्तों के लिए या तो बंद करना पड़ा अथवा उन्हें शेल्टर होम में तब्दील किया गया। इस दौरान वांछित बच्चों तक मिड-डे मील नहीं पहुँच पाया। तेज़ गर्मी और तेज़ सर्दियों में शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों को एक निश्चित समय के लिए बंद कर दिया जाता है। अक्सर ये समय एक हफ्ते से 3 हफ़्तों तक का होता है। इस दौरान भी बच्चों के पोषण को लेकर गंभीर चुनौतियों का सामना ये परिवार करते हैं।

- **टेक होम राशन (टीएचआर):** टीएचआर का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और छह साल से कम उम्र के बच्चों को पूरक पोषण प्रदान करना है। हालांकि, तेज़ गर्मी या तेज़ बारिश/जल भराव की घटनाओं के दौरान अक्सर टेक होम राशन की आपूर्ति में व्यवधान और वितरण में देरी देखी गयी है। यह भी देखा गया है कि प्रवासी परिवार हमेशा अपने नए स्थानों पर टीएचआर प्राप्त करने के लिए पंजीकृत नहीं हो पाते, जिस से वे इसका लाभ नहीं ले पाते।

  आंगनवाड़ी केंद्र पर टेक होम राशन लेने का इंतज़ार करती महिलायें
  (फोटो- ओम, देवाली आंगनवाड़ी केंद्र)

  बदलते मौसम में सबसे ज्यादा आंगनवाडी केंद्र ही अस्थायी तौर पर बंद कर दिए जाते है और केंद्र के स्टाफ को राहत कार्यों में लगा दिया जाता है। ऐसे में केंद्र की सुविधाएं बच्चों तक नहीं पहुँच पाती। यह भी देखने में आया है कि तेज़ बारिश या आयड नदी में ज्यादा पानी आने पर कई कच्ची बस्तियों (खासकर कृष्णपुरा, अलीपुरा, स्वराज नगर, लोहार बस्ती, गोवलिया बंजारा बस्ती आदि) को खाली करवा कर सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया जाता है। कई बार ये परिवार स्वयं अपने स्तर पर अपने परिचितों के यहाँ अन्य जगहों या गांवों में चले जाते हैं। ऐसे में भी आंगनवाडी केंद्र की सेवाओं से वंचित हो जाते हैं।

उदयपुर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू करने में चुनौतियाँ

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) को विशेष रूप से कमज़ोर आबादी के लिए खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया था। हालाँकि, इस सर्वे के दौरान उदयपुर में इसके कार्यान्वयन में कई चुनौतियाँ सामने आई।

- **सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) लिंकेज और लाभार्थी पहचान:** उदयपुर में पात्र लाभार्थियों की पहचान करना एक बड़ी समस्या है। कई प्रवासी परिवार और असंगठित क्षेत्र के श्रमिक उचित दस्तावेज़ों की कमी या राशन कार्ड से नाम जुड़े न होने के कारण पीडीएस से बाहर रह जाते हैं। यदि घर के मुखिया की फिंगरप्रिंट या चेहरा रिकॉर्ड से मेल नहीं खाता तो कई-कई महीनों तक पूरे परिवार को राशन नहीं मिलता। पिछले साल २०२४ में आये नए नियमों के अनुसार पूरे परिवार का केवाईसी (KYC) करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे में यदि परिवार का एक भी सदस्य उदयपुर से बाहर प्रवास पर है तो पूरे परिवार को इस योजना का लाभ नहीं मिलता। मौसम में बदलाव के कारण कई बार परिवार के सदस्यों को नजदीकी बड़े शहरों में काम की तलाश में जाना पड़ता है।

  यह भी एक सच है कि अभी भी **जनगणना २०११ के अनुसार अल्प आय वर्ग (बीपीएल) को निर्धारित** किया गया है। ऐसे में कई परिवार इस योजना से सीधे सीधे बाहर है। नए नियमों में यदि किसी परिवार के पास २००० स्क्वायर फीट का पक्का मकान है अथवा घर में वाहन है तो भी उन्हें इस योजना से वंचित कर दिया जाता है। प्रवासी परिवारों के पास या अल्प आय वर्ग के पास (आसान किश्तों के इस दौर में) एक मोटरसाईकिल होना आम है; ऐसे में भी इन परिवारों को लाभ नहीं मिलता। ICLEI के साथियों ने इस दौरान पीडीएस केन्द्रों का भी दौरा किया; इस दौरान ऐसे कई केस सामने आये।

  कई मोहल्लों में पीडीएस दुकानें ही नहीं है; ऐसे में उन्हें ३-५ किलोमीटर दूर जाकर राशन लेना होता है। तेज़ गर्मी या तेज़ बारिश के समय में यह आवागमन कैसे होगा, इस ओर फ़िलहाल प्रशासन को ध्यान दिया जाना ज़रूरी है।

- **गुणवत्ता, भंडारण और परिवहन के मुद्दे:** अत्यधिक गर्मी और शहरी बाढ़ से खाद्यान्नों के भंडारण और परिवहन में बाधा आती है। उच्च तापमान से संग्रहीत अनाज की गुणवत्ता प्रभावित होती है, जबकि बाढ़ से अक्सर सड़कें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और वितरण में देरी होती है। खराब भंडारण की स्थिति से भी खाद्यान्नों की गुणवत्ता में गिरावट आती है, जिससे वे कम पौष्टिक और कभी-कभी उपभोग के लिए असुरक्षित हो जाते हैं। यह बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण को असमान रूप से प्रभावित करता है।

- **पोषण की अपर्याप्तता और असमान वितरण:** पीडीएस के तहत वितरित खाद्यान्न में अक्सर विविधता और आवश्यक पोषक तत्वों की कमी होती है, जिससे बच्चों और अन्य कमज़ोर समूहों की आहार संबंधी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं। यह अपर्याप्तता कुपोषण की दरों को बढ़ाती है। उल्लेखनीय है कि योजना के तहत प्रत्येक व्यक्ति पर केवल ५ किलो गेंहू प्रति माह के अनुसार मिलता है, जबकि बढ़ते बच्चों और गर्भवती-धात्री महिलाओं को प्रोटीन और अन्य पोषक तत्वों की भी आवश्यकता होती है। यदि कोई महिला अकेली रह रही है तो उसे केवल ५ किलो गेंहू में पूरे माह गुज़ारा करना काफी मुश्किल होता है।

खेतीबाड़ी पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव

शहर और आस पास के इलाके आज भी खेती-बाड़ी पर काफी हद तक निर्भर हैं। ये अपनी रसोई के लिए गेंहू और मक्का जैसी फसलें लेते हैं, जबकि शेष समय में नदी पेटे में सब्जियां उगाते हैं। ये खेती-बाड़ी मानसून की बारिश और नदी के जल पर बहुत अधिक निर्भर करती है और इस कारण बदलते मौसम का बहुत ज्यादा प्रभाव इस पर पड़ता है। मक्का, गेहूँ और दालों जैसी प्रमुख खाद्यान्न फसलों की पैदावार अनियमित वर्षा पैटर्न और लंबे समय तक सूखे के

कारण कम हुई है। लकडवास, कलडवास, मादड़ी, बड़गांव, बेदला आदि क्षेत्रों में नदी के पेटे में सब्जियों की खेती अक्सर बाढ़ के कारण नष्ट हो जाती है। खेती-बाड़ी में जलवायु के कारण होने वाले ये व्यवधान सीधे तौर पर खाद्य उपलब्धता और सामर्थ्य को खतरे में डालते हैं, जिससे एक ऐसा प्रभाव पैदा होता है जो परिवारों के लिए खाद्य असुरक्षा को बढ़ाता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी आय सीमित है और जिनके पास पौष्टिक भोजन तक पहुँच नहीं है।

पालिसी आधारित सिफारिशें और अनुकूलन रणनीतियाँ

उदयपुर में खाद्य सुरक्षा और बाल पोषण पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए, एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। एक तरफ जहाँ प्रभावित होने वाले क्षेत्रों के लिए विशेष नीति निर्माण की ज़रूरत हैं, वहीँ जलवायु बदलाव के कारण कमज़ोर होती वितरण प्रणालियों को मज़बूत करने और उनकी मोनिटरिंग मज़बूत करने की आवश्यकता है। सार्वजनिक वितरण व्यवस्था में भंडारण सुविधाओं में सुधार, वितरण को सुव्यवस्थित करने और बदलते जलवायु के कारण उत्पन्न आकस्मिक स्थितियों प्रभावी योजनाओं की स्थापना करके यह सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि सरकारी खाद्य आपूर्ति तंत्र जलवायु के अनुकूल हैं।

प्रवासी परिवारों को खाद्य अधिकार प्रदान करने के लिए तंत्र विकसित किया जाना भी ज़रूरी है। बच्चों और माताओं को फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थ और सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान करने वाले कार्यक्रमों का विस्तार करना भी आवश्यक है, ताकि भोजन की कमी के समय भी पोषण संबंधी ज़रूरतें पूरी हों। प्रवासी बच्चों के लिए विशेष पहल की जा सकती है ताकि उन्हें स्कूल-आधारित और समुदाय-आधारित पोषण कार्यक्रमों में शामिल किया जा सके।

नदी के आस-पास रहने वाले परिवारों की सुरक्षा के लिए निगरानी और प्रारम्भिक चेतावनी सिस्टम को भी मज़बूत किया जाना आवश्यक है। बच्चे ऐसे स्थानों की तरफ नहीं जा पाए, यह भी तय किया जाना चाहिए। साल २०२४ में एक ७ साल की बच्ची तेज़ रफ्तार से बह रही आयड नदी में मछली पकड़ने गयी और पानी में बह गयी।

उदयपुर में जलवायु बदलाव से बच्चों के पोषण और खाद्य सुरक्षा पर फ़िलहाल एक व्यापक अध्ययन की आवश्यकता है, जो मौसम के बदलावों, बच्चों के पोषण, खाद्य सुरक्षा, पलायन आदि के मध्य अंतर्संबंध और सम्बंधित चुनौतियों की व्याख्या करे। इन विषयों पर काम करने के लिए सरकारी एजेंसियों-विभागों, सामाजिक- सामुदायिक संस्थाओं, उदयपुर नगर निगम और उदयपुर विकास प्राधिकरण के साथ-साथ स्थानीय समुदायों को साथ लाते हुए एक समन्वित दृष्टिकोण की ज़रूरत है। जलवायु-लचीली पद्धतियों को लागू करके, खाद्य आपूर्ति तंत्र को मजबूत करके और बाल पोषण को प्राथमिकता देकर, उदयपुर अपने बच्चों के लिए अधिक सुरक्षित और टिकाऊ भविष्य का निर्माण कर सकता है।

चलते चलते,

एक कच्ची बस्ती में साथ घूमते-घूमते अचानक आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता बोल पड़ी, "मौसम की मार उन लोगों के लिए कितने मायने रखती होगी, जिन्हें रोज़ कुंआ खोदना है और रोज़ पानी पीना है! २ दिन लू लगने से बीमार हो जाए तो परिवार सड़क पर आ जाता है। सरकार सिर्फ गेंहू देती है और हमको कहती है कि बच्चा कुपोषित नहीं होना चाहिए। आप कहते हो- बच्चे को दालें खिलाओ- शाक भाजी खिलाओ !! इतनी तेज़ गर्मी में ये लोग घर कैसे चलाये और बच्चों को क्या खिलाये?" मेरी तरफ देखते हुए वो थोड़ी देर जवाब का इंतज़ार करती रही और फिर आगे चल पड़ी। जवाब के लिए शायद बहुत काम करने की ज़रूरत को वो भी समझ रही होगी....!!

आलेख: ओम प्रकाश
ICLEI साउथ एशिया, उदयपुर